Features of DPSP :

- DPSPs are guidelines or principles given to the State to frame laws and policies./ नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को कानून और नीतियाँ बनाने के लिए दिए गए दिशानिर्देश या सिद्धांत हैं।
- Aim to establish social and economic democracy./ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य।
- Non-justiciable but fundamental in governance/ न्यायोचित नहीं, लेकिन शासन में मौलिक
- The directive Principles though non-justiciable in nature, but help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law./ निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायोचित नहीं हैं, लेकिन ये न्यायालयों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जाँच और निर्धारण में सहायता करते हैं।

Objectives of DPSP :

- To ensure social, economic, and political justice.
  सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना।
- To reduce inequality of income, status, and opportunities.
  आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को कम करना।
- To promote welfare of the people.
  जन कल्याण को बढ़ावा देना।
- To provide the foundation for economic democracy.
  आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखना।

Classification of DPSP :

Socialistic Principles/समाजवादी सिद्धांत:

- These principles reflect the ideology of socialism./ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को प्रतिबिम्बित करते हैं।
- They lay down the framework of a democratic socialist state, aim at providing social and economic justice./ ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है।

Articles : 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47

Gandhian Principles/गांधीवादी सिद्धांत:

- These principles are based on Gandhian ideology/ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं।
- They represent the program of reconstruction enunciated by Gandhi during national movement./ ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Articles : 40, 43, 43B, 46, 47, 48

Liberal- Intellectual Principles/उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत:

- These are inspired by liberal democracies of the West and aim to establish political and international justice./ ये पश्चिमी उदार लोकतंत्रों से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्थापित करना है।

Articles : 44, 45, 48A, 49, 50, 51

Important Amendments in Directive Principles :

The 42nd Amendment Act of 1976 added four new Directive Principles to the Original list./ 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में चार नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े।

- To secure opportunities for healthy development of children [Article 39(f)]./ बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना [अनुच्छेद 39(f)]।
- To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor [Article 39(A)]/ समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना [अनुच्छेद 39(ए)]।
- To take steps to secure the participation of workers in the management of industries [Article 43(A)]./ उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना [अनुच्छेद 43(ए)]।
- To protect and improve the environment and to safeguard forests and wild life [Article 48(A)]./ पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करना [अनुच्छेद 48(ए)]।

The 44th Amendment Act of 1978 added one more directive principle i.e. the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities (Article 38)/1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने एक और नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा, अर्थात राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करेगा (अनुच्छेद 38)।

The 86th Amendment Act of 2002 changed the subject – matter of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A./ 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया।

The 97th Amendment Act of 2011 added a new directive principle relating to co-operative societies.[Article 43(B)]/2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा [अनुच्छेद 43(B)]।

Difference Between Fundamental Rights and DPSP

Fundamental Rights	Directive Principles
1. These are negative as they prohibit the state from doing certain things	1. These are positive as they require the state to do certain things.
2. These are justiciable in nature	2. These are non-justiciable in nature
3. They aim at establishing political democracy in the country	3. They aim at establishing social and economic democracy in the country
4. They promote the welfare of the individual	4. They promote the welfare of the community. They are societarian and socialistic.
5. They do not require any legislation for their implementation	5. They require legislation for their implementation.
6. The courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental Rights as unconstitutional and invalid	6. The courts cannot declare a law violative of any of the directive Principles as unconstitutional and invalid.
7. They have legal sanctions	7. The have moral and political sanctions.

मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच अंतर

मौलिक अधिकार	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
1. ये नकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं।	1. ये सकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने हेतु निर्देश देते हैं।
2. इनका स्वरूप न्यायालय में लागू करने योग्य (न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय) होता है।	2. इनका स्वरूप न्यायालय में लागू न करने योग्य (अप्रवर्तनीय) होता है।
3. इनका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।	3. इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
4. ये व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।	4. ये समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये समाजवादी और सामुदायिक प्रकृति के होते हैं।
5. इनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती।	5. इनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है।
6. न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं।	6. न्यायालय नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकते।
7. इन्हें कानूनी प्रतिबंध का समर्थन प्राप्त है।	7. इन्हें नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त है।

Criticism of the Directive Principles

No legal force/ कोई कानूनी बल नहीं:

- The directive principles have been criticized mainly because of their non-justiciable nature./ निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना मुख्यतः उनके गैर-न्यायसंगत स्वभाव के कारण की गई है।
- KC Wheare called them as 'manifesto of aims and aspirations'./ के.सी. व्हेयर ने इन्हें 'उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणापत्र' कहा है।
- T.T. Krishnamachari describes the directives as 'a veritable dustbin of sentiments'/ टी.टी. कृष्णमाचारी ने निर्देशों को 'भावनाओं का वास्तविक कूड़ेदान' बताया है।
- K.T Shah called them with 'a cheque on a bank, payable only when the resources of the bank permit'./ के.टी. शाह ने इन्हें 'बैंक पर एक चेक के समान बताया है, जिसका भुगतान तभी किया जा सकता है जब बैंक के संसाधन अनुमति दें।'

टी.टी. कृष्णमाचारी

के.टी. शाह

Illogically arranged/अतार्किक रूप से व्यवस्थित:

- According to N. Srinivasan, ‘the directives are neither properly classified nor logically arranged./ एन. श्रीनिवासन के अनुसार, 'निर्देशिकाएँ न तो उचित रूप से वर्गीकृत हैं और न ही तार्किक रूप से व्यवस्थित हैं।'
- The declaration mixes up relatively unimportant issues with the most vital economic and social question./ यह घोषणापत्र अपेक्षाकृत महत्वहीन मुद्दों को सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के साथ मिला देता है।

Constitutional conflicts/संवैधानिक संघर्ष:

- K Santhanam has pointed out that the Directives lead to a constitutional conflicts/ के. संथानम ने बताया है कि ये निर्देशिकाएँ संवैधानिक संघर्षों को जन्म देती हैं।
- Between the centre and the states/ केंद्र और राज्यों के बीच
- Between the President and the Prime Minister/ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच
- Between the governor and the chief minister./ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच।

Conservative in nature/ रूढ़िवादी प्रकृति:

- According to Sir Ivor Jennings, the directives are based on the political philosophy of the 19th century England./ सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार, ये निर्देशिकाएँ 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं।
- Part IV of the constitution expresses ‘Fabian Socialism without the socialism’./ संविधान का भाग IV 'समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद' को व्यक्त करता है।

Landmark Cases

DPSP

- Champakam Dorairajan (1951) – FRs prevail over DPSPs
- चंपकम दोराईराजन (1951) - एफआर, डीपीएसपी पर हावी हैं
- Kesavananda Bharati (1973) – Harmony is basic structure/ केशवानंद भारती (1973) - सामंजस्य बुनियादी संरचना है
- Minerva Mills (1980) – Balance is essential between FRs & DPSPs/ मिनर्वा मिल्स (1980) - एफआर और डीपीएसपी के बीच संतुलन आवश्यक है

Question : 1

Which part of the Constitution of India describes the model of welfare state?

भारतीय संविधान का कौन-सा भाग कल्याणकारी राज्य के मॉडल का वर्णन करता है?

a) Fundamental Rights/मौलिक अधिकार

b) Fundamental Duties/मौलिक कर्तव्य

c) The Preamble/प्रस्तावना

d) Directive Principles of State Policy/राज्य के नीति निदेशक तत्व

IAS Pre 2020, SSC CGL T-2 02/03/2023

Question : 2

Art 44

What does the Uniform Civil Code primarily aim to achieve?

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) Strengthen federalism / संघवाद को मजबूत करना

b) Equal rights across all religions / सभी धर्मों में समान अधिकार सुनिश्चित करना

c) Promote religious autonomy / धार्मिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना

d) Protect minority rights / अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना

[Ssc phase 13, 01/08/2025]

ANSWER: (B)

Question : 3

What is the primary objective of a Uniform Civil Code (UCC)?

समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

a) Common criminal law for all / सभी के लिए समान आपराधिक कानून

b) Unify tax laws / कर कानूनों का एकीकरण

c) Common personal laws for all citizens / सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून

d) Standardize administrative procedures / प्रशासनिक प्रक्रियाओं का मानकीकरण

[SSC CGL Tier 1, 13 Sep 2025, Shift-1]

ANSWER: (C)

Question : 4

Which of the following article of the Indian Constitution promotes equal justice and free legal aid?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है?

a) Article 39A / अनुच्छेद 39A

b) Article 38 / अनुच्छेद 38

c) Article 42 / अनुच्छेद 42

d) Article 45 / अनुच्छेद 45

[SSC CHSL, 12 Nov 2025, Shift-3]

ANSWER: (A)

Question : 5

The concept of "Directive Principles of State Policy (DPSP)" in the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of which country?

भारतीय संविधान में "राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP)" की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?

a) Ireland / आयरलैंड

b) United States of America / संयुक्त राज्य अमेरिका

c) United Kingdom / यूनाइटेड किंगडम

d) Canada / कनाडा

[SSC Steno, 08/08/2025, Shift-1]

ANSWER: (A)

Question : 6

Which of the following is true about Fundamental Rights and DPSPs?

मौलिक अधिकार और राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSPs) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

a) Both are justiciable and enforceable / दोनों न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं

b) DPSPs override Fundamental Rights / DPSPs मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं

c) Fundamental Rights justiciable, DPSPs not / मौलिक अधिकार न्यायसंगत (justiciable) हैं, DPSPs नहीं

d) DPSPs guaranteed, Fundamental Rights optional / DPSPs सुनिश्चित हैं, मौलिक अधिकार वैकल्पिक हैं

[SSC CGL Tier 1, 12 Sep 2025, Shift-1]

ANSWER: (C)

Question : 7

Article 50 is part of which section of the Constitution?

अनुच्छेद 50 संविधान के किस भाग का हिस्सा है?

a) Fundamental Duties / मौलिक कर्तव्य

b) Directive Principles / राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

c) Fundamental Rights / मौलिक अधिकार

d) Preamble / प्रस्तावना

Part IV

Seperation of Judiciary & Executive

[SSC CGL Tier 1, 16 Sep 2025, Shift-1]

ANSWER: (B)

Question : 8

Article 40 of the Indian Constitution is related with:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है?

a) Organization of village panchayats / ग्राम पंचायतों का संगठन

b) Free and compulsory education / निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

c) Free housing to the poor / गरीबों को निःशुल्क आवास

d) Free medical aid to the citizen / नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता

[SSC CHSL, 27 Nov 2025, Shift-3]

ANSWER: (A)

Question : 9

DPSP

Consider the following statements:

I. They are not enforceable by any court.

II. It shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. ये किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।

II. कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

a) Only I/केवल I

b) Only II/केवल II

c) Both I and II/I और II दोनों

d) Neither I nor II/न तो I और न ही II

[SSC CHSL, 26 Nov 2025, Shift-3]

ANSWER: (C)

Question : 10

Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates __

भारतीय संविधान के अनुसार, धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है?

a) The Right to Equality/समानता का अधिकार

b) The DPSPs/राज्य के नीति निदेशक तत्व

c) The Right to Freedom/स्वतंत्रता का अधिकार

d) The concept of welfare/कल्याण की अवधारणा

IAS Pre 2021

ANSWER: (B)

Question : 11

Which article of the Indian Constitution says that DPSPs are not enforceable by any court?
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं?

a) Article 39/अनुच्छेद 39
b) Article 38/अनुच्छेद 38
c) Article 36/अनुच्छेद 36
d) Article 37/अनुच्छेद 37

Jharkhand PCS 2023

ANSWER: (D)

Question : 12

Identify the correct pair mentioning the Directive Principles of State Policy in the Constitution of India.

भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित सही जोड़ी की पहचान करें।

a) Equal justice and free legal aid – Article 42 / समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता – अनुच्छेद 42

b) Organisation of agriculture and animal husbandry – Article 43/कृषि एवं पशुपालन का संगठन – अनुच्छेद 43

c) Organisation of village panchayat – Article 41 / ग्राम पंचायतों का संगठन – अनुच्छेद 41

d) Equal pay for equal work for both men and women – Article 39/पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन – अनुच्छेद 39

RAS Pre 2021

ANSWER: (D)

Question : 13

MGNREGA scheme has been launched as a part of implementing which one of the following Articles of the Indian Constitution?

मनरेगा योजना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन का हिस्सा है?

a) Article 43/अनुच्छेद 43
b) Article 45/अनुच्छेद 45
c) Article 47/अनुच्छेद 47
d) Article 50/अनुच्छेद 50

UP UDA

ANSWER: (A)

Question : 14

Which of the following Articles of the Constitution of India talks about the Uniform Civil Code (UCC)?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित है?

a) Article 43/अनुच्छेद 43

b) Article 44/अनुच्छेद 44

c) Article 45/अनुच्छेद 45

d) Article 46/अनुच्छेद 46

ANSWER: (B)

Question : 15

Which of the following Articles of the Constitution of India talks about the Uniform Civil Code (UCC)?

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित है?

a) Article 43/अनुच्छेद 43

b) Article 44/अनुच्छेद 44

c) Article 45/अनुच्छेद 45

d) Article 46/अनुच्छेद 46

Jharkhand PCS 2023

ANSWER: (B)

Writs & Types

5

By Varun Awasthi (GS Guru)

Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण)

- ✓ यह रिट (writ) उस अधिकारी (authority) के विरुद्ध दायर किया जाता है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर (detained) रखता है. इस रिट (writ) को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय (court) में पेश करे.
- ✓ **The Supreme Court or High Court can issue this writ against both private and public authorities.**
- ✓ **Habeas Corpus can not be issued in the following cases:**
  - ✓ **When detention is lawful**
  - ✓ **When the proceeding is for contempt of a legislature or a court**
  - ✓ **Detention is outside the jurisdiction of the court**

Mandamus (परमादेश रिट)

- ✓Unlike Habeas Corpus, Mandamus cannot be issued against a private individual
- ✓Mandamus can not be issued in the following cases:
  - ✓To enforce departmental instruction that does not possess statutory force
  - ✓To order someone to work when the kind of work is discretionary and not mandatory
  - ✓Mandamus can't be issued against the Indian President or State Governors
  - ✓Against the Chief Justice of a High Court acting in a judicial capacity

परमादेश

- बंदी प्रत्यक्षीकरण के विपरीत, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता।
- **<u>निम्नलिखित मामलों में परमादेश जारी नहीं किया जा सकता:</u>**
- ऐसे विभागीय निर्देश को लागू करना जिसमें वैधानिक बल न हो।
- किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य का आदेश देना जो विवेकाधीन हो और अनिवार्य न हो।
- भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता।
- न्यायिक क्षमता में कार्यरत किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध।

Prohibition (प्रतिषेध रिट)

- ✓यह रिट (writ) किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है. इस रिट (writ) को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है. इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है.
- ✓**Writ of Prohibition can only be issued against judicial and quasi-judicial authorities.**
- ✓**It can't be issued against administrative authorities, legislative bodies and private individuals or bodies.**

Certiorari (उत्प्रेषण लेख)

- ✓ यह रिट (writ) भी अधीनस्थ न्यायालयों (sub-ordinate courts) के विरुद्ध जारी किया जाता है. इस रिट (writ) को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय को भेजें. उत्प्रेषण लेख का मतलब उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मुक़दमे के प्रलेख (documents) की समीक्षा (review) मात्र है
- ✓ **Before 1991: The writ of Certiorari used to be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities**
- ✓ **After 1991: The Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against administrative authorities affecting the rights of individuals**
- ✓ **It cannot be issued against legislative bodies and private individuals or bodies.**

DPSP & Practice + Writ

Quo Warranto (अधिकार पृच्छा)

- ✓उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद (public post) को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है
- ✓**Quo-Warranto can be issued only when the substantive public office of a permanent character created by a statute or by the Constitution is involved**
- ✓**It can't be issued against private or ministerial office**

Supreme Court VS High Court

- ✓Article 32 & 226
- ✓Supreme Court: Only in Fundamental Rights
- ✓High Court: Fundamental Rights + Legal Rights
- ✓Before 1950, only the High Courts of Calcutta, Bombay and Madras had the power to issue the writs (Fact)